

विराट भूमि

[शहडोल | बुढ़ार | धनपुरी | ब्योहारी | जयसिंहनगर | बाणसागर]

समिति प्रबंधक के बिगड़े बोल से मचा बवाल

वायरल ऑडियो के बाद किसानों का फूटा गुस्सा

स्थानांतरण और कार्रवाई की उठी मांग

करोड़ों के भ्रष्टाचार के पुराने आरोप भी फिर चर्चा में

शहडोल। जिले की लैप्स प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, टिकरी एक बार फिर गंभीर विवादों में घिर गई है। इस बार मामला केवल किसानों से कथित अभद्र व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग ने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बना दिया है। भाजपा पदाधिकारियों ने जिला भाजपा अध्यक्ष को विस्तृत शिकायत पत्र सौंपते हुए समिति प्रबंधक के तत्काल स्थानांतरण, निष्पक्ष जांच और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। शिकायत सामने आने के बाद क्षेत्र में किसानों के बीच भारी आक्रोश बनाया जा रहा है। शिकायत के अनुसार समिति प्रबंधक रघुनंदन तिवारी (उर्फ पुजारी जी) पर किसानों से कथित रूप से अमर्यादित भाषा में बातचीत करने का आरोप लगाया गया है। वायरल ऑडियो को लेकर शिकायतकर्ताओं का कहना है कि एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कथित भाषा का प्रयोग न केवल प्रशासनिक मर्यादा के विपरीत है, बल्कि किसानों के सम्मान को भी ठेस पहुंचाने वाला है। क्षेत्र में वायरल हो रही इस ऑडियो ने किसानों और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों के बीच नाराजगी का माहौल पैदा कर दिया है। शिकायत में ग्राम बराड़ निवासी किसान अशोक कहार का भी उल्लेख किया गया है। आरोप लगाया गया है कि किसान ने खाद खरीदने के लिए समिति में 10,775 जमा किए थे, लेकिन समय पर राशि खाते में दर्ज नहीं हुई। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जब किसान ने इसकी जानकारी लेनी चाही तो उसके साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया। इस मामले की रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज



कराए जाने का भी उल्लेख शिकायत पत्र में किया गया है।

मर्यादा मूले प्रबंधक, किसानों से कथित अमद्रता पर मडका आक्रोश

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों के सम्मान और कल्याण की बात कर रही हैं, ऐसे समय में यदि सहकारी संस्था का जिम्मेदार अधिकारी किसानों के साथ कथित रूप से अपमानजनक व्यवहार करता है तो यह पूरे सहकारिता तंत्र पर सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि ऐसे अधिकारी किसानों का विश्वास कमजोर करते हैं और शासन की मंशा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

भ्रष्टाचार के पुराने आरोप भी फिर आए चर्चा में

वायरल ऑडियो के बाद अब समिति प्रबंधक पर पहले से लगते रहे भ्रष्टाचार के आरोप भी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। क्षेत्र में लंबे समय से समिति के संचालन, वित्तीय लेन-देन और कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि प्रबंधक पर पूर्व में भी कई गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि किसी सक्षम जांच एजेंसी द्वारा सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है।

करोड़ों के भ्रष्टाचार, अकूत संपत्ति के आरोप

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि समिति प्रबंधक ने अपने कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार कर भारी चल-अचल संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने मांग की है कि केवल वायरल ऑडियो ही नहीं, बल्कि प्रबंधक की संपत्ति, वित्तीय लेन-देन, समिति के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य अभिलेखों की भी गहन जांच कराई जाए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और इनकी सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

सीसीटीवी फुटेज और अभिलेखों की जांच की मांग

भाजपा पदाधिकारियों ने मांग की है कि वायरल ऑडियो को प्रारंभिक साक्ष्य मानते हुए निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही समिति परिसर के सीसीटीवी फुटेज, वित्तीय अभिलेखों और उपलब्ध दस्तावेजों की भी जांच की जाए ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। शिकायत में कहा गया है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

स्थानांतरण की मांग भी हुई तेज

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि निष्पक्ष जांच तभी संभव होगी जब संबंधित प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। उनका तर्क है कि जांच के दौरान पद पर बने रहने से साक्ष्यों और गवाहों पर प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रह सकती है। इसलिए किसानों के हित और प्रशासनिक पारदर्शिता को देखते हुए स्थानांतरण आवश्यक है।

अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी निगाहें

लगातार सामने आ रही शिकायतों, वायरल ऑडियो और भाजपा संगठन द्वारा दिए गए शिकायत पत्र के बाद अब पूरा मामला प्रशासन के पाले में है। क्षेत्र के किसान और स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। यदि जांच में शिकायत पत्र में लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो सकती है। वहीं, यह भी उल्लेखनीय है कि समिति प्रबंधक पर लगाए गए भ्रष्टाचार, अभद्र व्यवहार और अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप शिकायतकर्ताओं के दावे हैं, जिनकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

खबर संक्षेप

नल-जल योजना के लापरवाह ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश



शहडोल। जिले की सोहागपुर जनपद की ग्राम पंचायत लालपुर में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम के तहत आयोजित जनसंवाद व उद्योग संवाद में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब प्रशासनिक अमले ने जनसमस्याओं को लेकर सीधे अफसरों की क्लास लगा दी। विधायक जयसिंह मरावी, नवागत कलेक्टर पार्थ जायसवाल एवं पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल की मौजूदगी में आयोजित इस जन-अदालत में ग्रामीणों ने जल संकट अदालत में ग्रामीणों ने जल संकट से लेकर लचर शिक्षा व्यवस्था तक के मुद्दों की झड़ी लगा दी, जिस पर कलेक्टर ने ऑन-द-स्पॉट सख्त फैसले सुनाए।

जनसंवाद के दौरान लालपुर के ग्रामीणों ने गांव में पेयजल संकट का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। ग्रामीणों ने बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत नल-जल योजना का कार्य निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बाद भी अधूरा पड़ा है। इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने पीएचई अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने मौके पर ही निर्देश दिए कि लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर अनुबंध राशि का 10 प्रतिशत जुर्माना ठोका जाए और उसे तत्काल ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डालने की कड़ी कार्रवाई की जाए।

शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही की शिकायत करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य अक्सर स्कूल से नदारद रहते हैं। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को प्राचार्य के खिलाफ तत्काल जांच बैठाने के आदेश दिए। वहीं गांव के अधूरे सामुदायिक भवन के काम को ग्राम पंचायत द्वारा अविलंब पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। लोहागढ़िया मोहल्ले में जर्जर बिजली पोल और झूलते तारों को तुरंत बदलने के निर्देश बिजली विभाग को दिए गए। किसान सम्मान निधि, पीएम आवास, पेंशन, सीमांकन, बंटवारा व फौती नामांतरण के लॉंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए नायब तहसीलदार को पाबंद किया गया।

मानसून में सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं शहडोल चौपाटी में खाद्य विभाग का ताबड़तोड़ छापा, कड़ा अल्टीमेटम!

सीएमएचओ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा

अमले की सर्जिकल स्ट्राइक

तेल, मसालों और साफ-सफाई पर कड़ा

पहरा, गिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा

शहडोल। मानसून की दस्तक के साथ ही शहर में पेट और स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। आम नागरिकों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मुहैया कराने के इरादे से खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले में चेंकिंग का चाबुक चला दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा के सख्त रुख के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी वाजिद मोहिद की अगुवाई में टीम ने शुरूवार को शहडोल चौपाटी पर अचानक दबिश देकर हड़कंप मचा दिया।

चाट, मोमोज और डोसा स्टॉलों की हुई सर्जिकल स्ट्राइक

शुक्रवार की शाम चौपाटी के खाद्य स्टॉलों पर रोज की तरह ग्राहकों की चहल-पहल थी, तभी विभाग की टीम ने चाट, मोमोज, चाइनीज फास्ट फूड, इटली-डोसा समेत दर्जनों दुकानों को घेरकर औचक निरीक्षण शुरू कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर खाद्य पदार्थों का कच्चा माल, मसालों की शुद्धता, भंडारण की स्थिति और सबसे अहम बार-बार इस्तेमाल होने वाले री-यूज्ड तेल की गुणवत्ता को गहराई से परखा। टीम ने स्टॉल संचालकों को हद्दपार दी कि मानसून की नमी में जरा सी लापरवाही बीमारियों का सैलाब ला सकती है, इसलिए बासी भोजन और एक्सपायरी सामग्री को तुरंत कूड़ेदान के हवाले करें।

एग्रन और गलक्स बिना नहीं मिलेगा प्रवेश

निरीक्षण के दौरान अधिकारी वाजिद मोहिद ने दुकानदारों को कड़े लहजे में समझाया कि खाद्य सामग्री तैयार करने वाले कारीगरों और वेटरों को साफ-सुथरा एग्रन, हेड कैप (सिर का ढक्कन) और हैंड लव्स

शासकीय उचित मूल्य दुकान समय एवं दिन निर्धारित कर खुलवाएं: कलेक्टर



कलेक्टर ने लोगों से संवाद कर, समस्याओं का त्वरित समाधान के दिए निर्देश

शहडोल। कलेक्टर पार्थ जायसवाल एवं पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल ने शासकीय उचित मूल्य दुकान धुरवार का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान में पात्र लोगों को खाद्यान्न वितरण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही स्थानीय लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याओं एवं शिकायतें सुनीं। कलेक्टर को लोगों ने ग्राम धुरवार में पानी की समस्या, खाद्यान्न वितरण का समय एवं तिथि निर्धारित नहीं होने पर राशन प्राप्त करने में समस्या होती है, भूमिया जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया। जिस पर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती अमृता गर्ग को समस्याओं की जांच कर त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय उचित मूल्य दुकान को संचालित करने हेतु प्रत्येक माह समय एवं तिथि निर्धारित कर लोगों को सूचना दें जिससे राशन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। कलेक्टर ने नल जल योजना के कार्यों, शासकीय उचित मूल्य दुकान में प्राप्त कर रहे हितवाहियों की संख्या, राशन उठाव, वितरण आदि की भी जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवम प्रजापति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती अमृता गर्ग सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

उद्योग संवाद के माध्यम से युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार हेतु किया प्रेरित

शहडोल। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जनपद पंचायत सोहागपुर के 12 कलस्टरो में शिविरो का आयोजन किया गया। कलेक्टर पार्थ जायसवाल, पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल तथा सीईओ जिला पंचायत शिवम प्रजापति ने कलस्टर धुरवार में ग्राम पंचायत भवन में आयोजित शिविर में पहुंचकर लोगों से शासन की विभिन्न जगहितकारी योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, सबल कार्ड, अनुगृह सहायता, फौती, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा,राषन वितरण, आयुष्मान कार्ड, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति, उर्वरक की उपलब्धता आदि के संबंध में जानकारी ली।

संवाद के लिए ग्रामीणो ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त होता है लेकिन दुकान संचालित करने हेतु समय एवं दिन निश्चित नहीं है। कई ग्रामीणो के द्वारा बताया गया कि जमीन का बंटवारा नहीं होने से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी

कलेक्टर ने अपने समक्ष कराई हीमोग्लोबिन की जांच स्वास्थ्य सेवाओं की ली जानकारी

शहडोल। कलेक्टर पार्थ जायसवाल एवं पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धुरवार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र में आए मरीजों से चर्चा कर स्वास्थ्य केंद्र में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की तथा अपने समक्ष हीमोग्लोबिन की जांच कराई। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध रहे। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले व्यक्तियों की सिकल सेल एनीमिया की भी जांच सुनिश्चित की जाए जिससे जिले को सिकल सेल एनीमिया मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने अनमोल पोर्टल में दर्ज जानकारी, सिकल सेल एनीमिया की जांच, एनवैडजोल की दवाई खिलाने, स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित स्टॉफ सहित अन्य जानकारीयां भी प्राप्त की। कलेक्टर ने ओपीडी कक्ष, टेस्टिंग रूम सहित अलकक्षों का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवम प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती अमृता गर्ग सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



विद्यार्थियों को प्रदाय करें प्रोटीनयुक्त आहार: कलेक्टर कलेक्टर बने शिक्षक सिखाएं गणित के प्रश्न,परखी शिक्षा गुणवत्ता

कलेक्टर ने शासकीय कन्या आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण

शहडोल। कलेक्टर पार्थ जायसवाल, पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवम प्रजापति ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 के प्रथम दिवस ग्राम पंचायत कंचनपुर में संचालित शासकीय कन्या आवासीय विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कक्षा 11वीं के गणित के क्लासरूम में पहुंचकर शिक्षक द्वारा तत्समय पढ़ाएं जा रहे त्रिकोणमिति के प्रश्नों को अपने समक्ष विद्यार्थी राजेश्वरी सिंह से हल करवाया, जिन्होंने प्रश्न को सही तरीके से हल किया। इस पर कलेक्टर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी विद्यार्थियों को लक्ष्य बनाकर मेहनत करने की समझाईश दी।

कलेक्टर ने आवासीय छात्रावास मे रहने वाली छात्राओं को प्रोटीनयुक्त आहार एवं फल, दूध भी समय-समय देने के निर्देश अधीक्षक को दिए। उन्होंने छात्रावास क्रमांक-1 में छात्राओं के रहने के लिए की गई व्यवस्थाओं तथा साफ-सफाई का भी जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए छात्रावास एवं विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए जिस पर प्राचार्य डीके श्रीवास्तव ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है। कलेक्टर ने आवासीय विद्यालय में रह रही बालिकाओं के लिए फुटबाल मैदान विकसित करने के निर्देश प्राचार्य को दिए। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती अमृता गर्ग, सहायक संचालकसंजय पाण्डेय, डीपीसी अमरनाथ सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



बिना नोटिस रोका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन जयसिंहनगर परियोजना में 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ वेतन कटौती का खेल

शहडोल। महिला एवं बाल विकास विभाग की जयसिंहनगर परियोजना इन दिनों अपनी अजीबो-गरीब और तुगलकी कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में है। जमीनी स्तर पर नौनिहालों की सेहत का ख्याल रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर जयसिंहनगर परियोजना के अफसर अपनी प्रशासनिक हनक दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आलम यह है कि छोटी-मोटी तकनीकी गड़बड़ी हुई नहीं कि अफसरों का चाबुक सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जेब पर चल जाता है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, परियोजना क्षेत्र में आए दिन सर्वर मेंटेंस, नेटवर्क समस्या या पोषाहार ट्रैकर ऐप की तकनीकी खराबी के कारण यदि कोई ऑनलाइन एंट्री अटक जाती है, तो अफसरों के पास जांच का वक्त नहीं होता। सीधे कटौती का फरमान सुना दिया जाता है। विभाग यह भूल जाता है कि गांव-देहात में सर्वर और नेटवर्क उनके घर की जागीर नहीं है, लेकिन तकनीकी लाचारी का पूरा ठीकरा आंगनबाड़ी



कार्यकर्ताओं के सिर ही फोड़ा जाता है।

हरैरानी की बात यह है कि पिछले 10 से 15 सालों के इतिहास में पहली बार जयसिंहनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की इतनी लंबी-चौड़ी ब्लैकलिस्ट तैयार की गई है, जिनके वेतन या तो पूरी तरह रोक दिए गए हैं या फिर भारी कटौती की गई है।

कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब काटकर और रात-दिन एक करके सभी तकनीकी कमियों को दूर कर दिया, फिर भी 3 से 4 महीनों से उनका रोका गया मानदेय उनके खातों में जमा नहीं किया गया। पहले से ही मामूली मानदेय पर काम करने वाली इन कार्यकर्ताओं के सामने अब अपने मासूम बच्चों का पेट पालना, बुजुर्गों की दवाई और घर का राशन जुटाना दूधर हो गया है।

किसी भी शासकीय व्यवस्था में वेतन काटने या रोकने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना अनिवार्य होता है, लेकिन जयसिंहनगर महिला बाल विकास परियोजना में तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ताक पर रख दिया गया है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि अफसरों की इस मनमानी और तानाशाही रवये के खिलाफ वे अब खामोश नहीं बैठेंगी। यदि बिना नोटिस रोके गए वेतन का अविलंब भुगतान नहीं किया गया और इस एकांतरफा तुगलकी फरमान पर रोक नहीं लगी, तो जयसिंहनगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सामूहिक रूप से काम बंद कर सड़कों पर उतरने को विवश होंगी।



ख़बर संक्षेप

ढीमरखेड़ा सीईओ करेंगे योजनाओं की समीक्षा

कटनी। मंगल भवन में द जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी युजवेंद्र कोरी योजनाओं को गति प्रदान करने समीक्षा करेंगे। श्री कोरी ने समस्त ग्राम पंचायतों के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, सहायक यंत्री, उपयंत्री, पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी और शाखा प्रभारी को समीक्षा बैठक में अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अवगत होवें कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान को लेकर जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अत्यंत जवाबदेही के साथ तत्परता पूर्वक आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के सीईओ श्री कोरी द्वारा मुख्यमंत्री जन विश्वासअभियान, सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का संछ्छि पूर्ण निराकरण, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, अनुग्रह सहायता, व्हीबी -जी राम जी योजना के अंतर्गत श्रमिक नियोजन में वृद्धि एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास पूर्णता, समग्र ई- केवाईसी एवं निर्धारित एजेंडा के अनुसार अन्य विषयों पर समीक्षा की जाएगी।

जिले में अब तक 374.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज**कटनी**। जिले में 1 जून से 6 अगस्त तक कुल 374.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। विस्ति हो कि पिछले आलोच्य अवधि के दौरान जिले में 726.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। इस अवधि के दौरान रीठी तहसील में रिकार्ड 973 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। इस वर्ष जिले में इस अवधि के दौरान सबसे अधिक औसत वर्षा स्लीमनाबाद तहसील में दर्ज की गई है, जहाँ अब तक 693.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी है। जिले में इस अवधि में अब तक कटनी तहसील में 375.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। जबकि तहसील रीठी में 542.8 मिलीमीटर, बड़वारा तहसील में 234.5 मिलीमीटर, बरही तहसील में 217.8 मिमी, विजयराघवगढ़ तहसील में 271.8 मिलीमीटर, बहोरीबंद तहसील में कुल 337.5 मिलीमीटर एवं स्लीमनाबाद तहसील में सर्वाधिक 693.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई वहीं ढीमरखेड़ा तहसील में 320.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है।

जुलाई माह का राशन नहीं मिलने से हितग्राही परेशान**सिलौड़ी**। ग्राम पंचायत देवरी बिछिया और रामपुर बरेली में जुलाई माह का राशन नहीं मिलने से हितग्राही परेशान हो रहे हैं। शासन के नियम अनुसार हर माह का राशन उसी माह में अंतिम तारीख तक वितरण हो ही जाना चाहिए । तहसील ढीमरखेड़ा की देवरी बिछिया और रामपुर बरेली पंचायतों परंतु 31 जुलाई तक सभी कार्ड धारी लोगों को राशन नहीं मिला है। सेल्समैन का कहना है कि शासन स्तर से अभी तक राशन नहीं मिला है ।गरीब वर्ग को परिवार के पालन पोषण में दिक्कत हो रही है रामपुर के गड्डू चौधरी ने बताया अभी अगस्त माह चल रहा है अभी तक हम सभी ग्रामवासी को जुलाई माह का राशन नहीं मिला है जिससे कारण परिवार को दिए ताकि पौधों को संरक्षित किया जा सके।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का मैदानी स्तर पर प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर के निर्देश पर जिला पंचायत के योजना प्रभारी अधिकारी ग्राम पंचायतों में सतत रूप से भ्रमण कर मैदानी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। बुधवार को व्हीबी-जी राम जी योजना के परियोजना अधिकारी ऋषि राज चढ़ार ने जनपद पंचायत कटनी और सहायक परियोजना अधिकारी मृगेन्द्र सिंह ने रीठी की ग्राम पंचायतों में पहुंचकर योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की स्थिति की नब्ज टटोली।

श्री चढ़ार ने ग्राम पंचायत सरसवाही, मड़ई और जुहला पहुंच कर व्हीबी, -जी राम जी योजना के अंतर्गत मां की बगिया के अंतर्गत कराए गए प्लांटेशन कार्य, खेत तालाब और सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने पौधों की देखभाल और सुरक्षा पर ध्यान रखने के साथ-साथ उद्यान विभाग के परामर्श से कीटनाशक दवायियों का छिड़काव करने के निर्देश ग्राम पंचायत को दिए ताकि पौधों को संरक्षित किया जा सके।

नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 प्रवेश का सुनहरा मौका



आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ी

अमरकंटक। विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2027 के तहत कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक विद्यार्थी 10 अगस्त 2026 तक नि:शुल्क ऑनलाइन आवेदन कर

सकेंगे। समिति द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2027-28 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 जुलाई 2026 से संचालित है। दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने तथा अधिक से अधिक अभ्यर्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवेदन की समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नवोदय विद्यालय समिति ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है। अभ्यर्थी

बिना स्वीकृत खदान कहां से आई मुरुम

कागजों में चकाचक खेल मैदान धरातल पर भ्रष्टाचार की गह्रा क्रांति!

उमरिया पंचायत में सरपंच-सचिव का मास्टर खेल

का झोल बनाया गया और गरीब मजदूरों के हक का पैसा सरपंच-सचिव की सरपरस्ती में चहेतों के खातों में डालकर आपस में बांट लिया गया।

अवैध उत्खनन का महावीर खेल

इस पूरे खेल मैदान घोटाले की सबसे बड़बूदार परत मुरुम आपूर्ति में खुलती है। नरेंगा के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार महावीर ट्रेडर्स के नाम पर बिल क्रमांक 702 में 19 दिसम्बर 2024 के जरिए 1110 घनमीटर मुरुम आपूर्ति के एवज में 1लाख 99 हजार 800 रुपये का भुगतान दर्ज है। हालांकि तकनीकी स्वीकृति में कुल 2550 घनमीटर मुरुम हेतु 4 लाख 59 हजार का प्रावधान था। लेकिन जब पूरे ग्राम पंचायत उमरिया या आस-पास के क्षेत्र सहित जिले में कोई भी सरकारी मुरुम खदान स्वीकृत ही नहीं है, तो आखिर फर्म संचालक ने यह मुरुम कहां से लाकर पंचायत को दी?

पर्यावरण को लगाया गया चूना

सबसे गंभीर विषय यह है कि भुगतान से पहले



जिम्मेदार अधिकारियों ने रॉयल्टी चालान की जांच क्यों नहीं की? बार रॉयल्टी सत्यापन और बिना खनिज अनुज्ञा पत्र के लाखों का भुगतान जारी कर देना सीधे-सीधे सरपंच, सचिव, तकनीकी अमले

और स्प्लायर फर्म की अपराधिक साठगांठ की ओर इशारा करता है।

तकनीकी मापदंडों की उड़ाई धजियां

तकनीकी एस्टीमेट की धजियां उड़ाने में भी निर्माण एजेंसी (ग्राम पंचायत) ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तकनीकी प्रावधानों के अनुसार मैदान में 80 से 100 किलोटन क्षमता के रोलर से रोलिंग कर 97 प्रतिशत डेंसिटी प्राप्त करनी थी, जिसके लिए रोलर और वाटर टैंकर (22.5 घंटे) का बजट स्वीकृत



समतलीकरण हुआ और नागरिक सूचना बोर्ड का तो नामो-निशान तक नहीं है। तकनीकी सत्यापन करने वाले उपयंत्री और सहायक यंत्री ने बिना धरातल देखे किस आंख से मूल्यांकित रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिए, यह भी एक संगीन जांच का विषय है।

शासकीय स्कूल के बगल में कचरा घर सरपंच और सचिव की अद्भुत दूरदर्शिता का नमूना देखना हो तो शासकीय प्राथमिक विद्यालय के पास चले आइए। बिना सोच-समझकर और बिना ग्रामीणों से सलाह लिए स्कूल के ठीक बगल में पंचायत द्वारा कचरा घर (कूड़ादान) ठोक दिया गया है। मौसम बरसात का है, कचरा सड़ रहा है और



डिजनीलैंड मेले में सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल



झूला हादसे, पार्किंग से साइकिल चोरी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से नाराजगी एसडीएम बोले कराई जाएगी जांच**कोतमा**। नगर के वार्ड क्रमांक-7 में

संचालित डिजनीलैंड मेले की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में बच्चे, महिलाएं और परिवार मनोरंजन के लिए मेले में पहुंच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर स्थानीय नागरिकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में सामने आए झूला हादसे और पार्किंग से साइकिल चोरी की घटना ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेले में आने वाले वार्हनों की सुरक्षा के लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। आरोप है कि चार दिन पहले पार्किंग क्षेत्र से एक साइकिल चोरी हो गई, जिससे लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। नागरिकों का कहना है कि यदि पार्किंग ही सुरक्षित नहीं है तो मेले में आने वाले परिवार खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे।

झूला हादसे ने बहाई चिंता

लोगों के अनुसार मेले में लगे यांत्रिक झूलों की नियमित तकनीकी जांच और सुरक्षा परीक्षण होना चाहिए। आरोप है कि चार दिन पूर्व एक झूला टूटने से जमुना कॉलरी निवासी एक परिवार के सदस्य घायल हो गए थे। घटना के बाद मेला प्रबंधन और पीडित पक्ष के बीच विवाद की स्थिति भी बनी। हालांकि इस मामले में अब तक किसी सक्षम विभाग की आधिकारिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं

हुई है, जिससे लोगों के मन में कई सवाल बने हुए हैं।

प्रवेश शुल्क तो लिया जा रहा, लेकिन सुविधाएं नदारद

मेले में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति 20 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है। कुछ लोगों का आरोप है कि टिकट पर शासकीय अनुमति अथवा कर संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। वहीं प्रवेश शुल्क

लेने के बावजूद शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण लोगों को पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

बारिश में अत्यवस्था, परिवारों को हो रही परेशानी

लगातार हो रही बारिश के बीच मेले में पर्याप्त शेड या सुरक्षित स्थान की व्यवस्था नहीं होने की शिकायत भी सामने आई है। बारिश शुरू होते ही लोग और छोटे बच्चे इधर-उधर भागते दिखाई देते हैं। महिलाओं और बुजुर्गों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

बिजली, फायर सेफ्टी और मेडिकल सुविधा पर भी सवाल

स्थानीय नागरिकों और सूत्रों का कहना है कि मेले के कुछ हिस्सों में खुले बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं, जो हादसे का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा फायर सेफ्टी, प्राथमिक उपचार केंद्र, आपातकालीन निकास मार्ग, सुरक्षित पार्किंग और पर्याप्त पेयजल जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं के अभाव की भी शिकायतें सामने आई हैं। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि मेले का संचालन निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए।

एसडीएम बोले कराई जाएगी जांच

इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) कोतमा टीआर नाग ने कहा कि उन्हें मेले में अव्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए जाएंगे। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बड़ी भीड़, इसलिए सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बने

प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए नागरिकों का कहना है कि प्रशासन को तत्काल मेले को निरीक्षण कर विद्युत सुरक्षा, झूलों की तकनीकी जांच, अतिशयमान व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, पार्किंग और अन्य आवश्यक इंतजामों की समीक्षा करनी चाहिए। लोगों का मानना ​​है कि समय रहते व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा होने का आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।



खबर संक्षेप

कुएं में गिरे जंगली सुअर के बच्चों का किया रेस्क्यू

कटनी। बड़वारा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिचपुरा में खेत में बने गहरे कुएं से जंगली सुअर के दो नन्हे गिर गये। सूचना मिलते ही हरकत में आई वन विभाग की टीम ने त्वरित और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों शावकों को सकुशल बाहर निकाला और उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह लगभग 8:00 बजे ग्राम बिचपुरा निवासी कृषक पुष्पराज कुशवाहा जब अपने खेत पर पहुँचे, तो उन्हें कुएं के अंदर जंगली सुअर के दो बच्चे दिखाई दिए। उन्होंने इसकी सूचना बड़वारा वन परिक्षेत्र कार्यालय को दी। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी के निर्देशन में विभाग का विशेष अमला तत्काल मौके पर पहुँचा। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कुएं में लगभग 2 से 3 माह की आयु के दो नन्हे शावक फँसे हुए हैं। मशक्कत के बाद दोनों शावकों को बिना किसी चोट के सकुशल बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू किए गए दोनों नन्हे शावकों का प्राथमिक परीक्षण करने के बाद, उन्हें सुरक्षित रूप से नजदीकी घने जंगल में छोड़ दिया गया।

कार्यालय में लगी आग, रिकॉर्ड को नहीं पहुंची क्षति

कटनी। महिला एवं बाल विकास परियोजना, कटनी शहरी कार्यालय परिसर में पूर्व में संचालित आधार सेंटर पर गुरुवार शाम लगभग 5:30 बजे लगी आग पर काबू पा लिया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी अब्दुल गफ्फार और परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना कटनी शहरी विद्या पाण्डेय ने बताया कि आग लगने के दौरान वहां रखे आधार सेंटर से संबंधित पुराने रस्तावेज, टेबल, कुर्सियां एवं अन्य कागजात जल रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही परियोजना कार्यालय के स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। परियोजना अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस घटना में महिला एवं बाल विकास परियोजना से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

घर के बाहर खड़ी स्कूटी को चोरों ने किया पार

कटनी। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मिशन चौक में रात के अंधेरे में बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी एक स्कूटी पार कर दी। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार मिशन चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने रहने वाले फरियादी शाहिद कुंरेशी की स्कूटी क्रमांक MP 21 ZD 9679 घर के बाहर खड़ी थी। रात में मौका पाते ही अज्ञात चोरों ने वाहन पर हाथ साज कर दिया। सुबह जब वाहन मालिक बाहर निकले तो स्कूटी गायब थी। मुख्य मार्ग और पेट्रोल पंप जैसे संवेदनशील स्थान के सामने से हुई इस चोरी ने पुलिसिया मुस्तेदी पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। फरियादी द्वारा मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चोरों का सुराग लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

तीनों स्कूलों को वॉटर फ्रिज की दी सौगात

सिलौंडी। सिलौंडी पंचायत ने तीनों शासकीय स्कूलों को छात्र छात्राओं को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने हेतु तीन वॉटर फ्रीज प्रदान किया है। सिलौंडी सरपंच पंचों संतोष कुमार, उपसरपंच राहुल राय ने तीन स्कूलों के प्राचार्य को वॉटर फ्रीज प्रदान किया है। सरपंच पंचों संतोष कुमार, उपसरपंच राहुल राय ने बताया कि छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा के साथ साथ शरीर को स्वास्थ्य रखने हेतु शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है। छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक सामग्री देने हेतु हम सभी संकल्पित है। इस दौरान संकुल प्राचार्य चंद्रकुमार परसवाल, कन्या हाई स्कूल प्राचार्य विशाल वरकडे, अशोक हल्दकार, राधा परस्ते, पंच फूला बाई मौजूद रहीं।

बरसात में भी उत्पादन जारी रखने के लिए दिन-रात जुटा प्रबंधन, उपक्षेत्रीय प्रबंधक मनीष सिंह की मॉनिटरिंग

मुनाफा दे रही अमलाई OCM कर्मचारियों को नहीं मिली पक्की सड़क की सौगात



धनपुरी। एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र की अमलाई ओपन कास्ट माईंस (ओसीएम) एक बार फिर अपनी उत्पादन क्षमता के कारण चर्चा में है। लगातार हो रही बारिश के बावजूद यहां कोयला उत्पादन और ओवरबर्डन (ओबी) हटाने का कार्य बिना रुके जारी है। खदान में कार्य कर रही आरकेटीसी कंपनी ने मानसून शुरू होने से पहले ही विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली थी, जिसके चलते भारी बारिश के बीच भी उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। पिछले दो दिनों से क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा के बीच उपक्षेत्रीय प्रबंधक मनीष सिंह स्वयं खदान के विभिन्न हिस्सों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। वे जलभराव, मशीनों की आवाजाही, ओवरबर्डन हटाने और कोयला परिवहन की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं। आरकेटीसी कंपनी के अधिकारियों के

साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बारिश के कारण उत्पादन और डिस्पैच पर कोई असर न पड़े।

मानसून से पहले की गई थी पूरी तैयारी

सूत्रों के अनुसार मानसून शुरू होने से पहले ही खदान में पानी निकासी, मशीनों की तैनाती, परिवहन मार्गों की मरम्मत और आवश्यक तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। यही वजह है कि लगातार बारिश के बावजूद उत्पादन का क्रम बना हुआ है और कोयला निकासी भी जारी है। लेकिन सड़क ने खेल दी विकास की पोल जहां उत्पादन व्यवस्था बेहतर दिखाई दे रही है, वहीं खदान तक पहुंचने वाली सड़क आज भी वर्षों पुरानी समस्या बनी हुई है। मुख्य प्रवेश द्वार से उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय तक करीब दो किलोमीटर लंबा

कच्चा मार्ग कर्मचारियों, अधिकारियों और ठेका श्रमिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। यह सड़क ओवरबर्डन की मिट्टी से बनी है। बारिश होते ही यह कीचड़ और फिसलन में बदल जाती है। इसी रास्ते से भारी डंपर, हाइवा, मशीनें और कर्मचारियों के दोपहिया वाहन गुजरते हैं। ऐसे में हर दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

हर बारिश के बाद ग्रेडर, फिर वही कहानी

बारिश के कारण सड़क खराब होने पर प्रबंधन द्वारा ग्रेडर मशीन से उसे समतल कराया जाता है, ताकि आवागमन फिर शुरू हो सके। लेकिन यह राहत कुछ दिनों की ही होती है। अगली बारिश के बाद सड़क फिर पहले जैसी हो जाती है और कर्मचारियों को परेशानी दोबारा शुरू हो जाती है।

2 किमी कच्ची सड़क पर हर दिन जोखिम उठाकर इयूटी पहुंच रहे कर्मचारी



'इयूटी से ज्यादा रास्ते का डर'

कर्मचारियों का कहना है कि बरसात के दिनों में सबसे बड़ी चुनौती इयूटी करना नहीं, बल्कि सुरक्षित तरीके से कार्यालय और कार्यस्थल तक पहुंचना है। दोपहिया वाहन फिसलने का डर हर समय बना रहता है। कई स्थानों पर कीचड़ इतना अधिक हो जाता है कि वाहन निकालना भी मुश्किल हो जाता है।

मुनाफे वाली खदान में सड़क क्यों नहीं?

श्रमिकों का कहना है कि अमलाई ओसीएम वर्षों से एसईसीएल के लिए बेहतर उत्पादन और राजस्व देने वाली खदानों में शामिल रही है। इसके बावजूद मुख्य सड़क का स्थायी निर्माण आज तक नहीं हो पाया। कर्मचारियों का मानना ​​है कि यदि इस मार्ग का डामरीकरण या कंक्रीटीकरण कर दिया जाए तो दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उत्पादन व्यवस्था भी और अधिक

सुचारु होगी।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

मुख्य गेट से उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय तक पक्की सड़क का तत्काल निर्माण। वर्षा जल निकासी की स्थायी व्यवस्था। दोपहिया वाहनों के लिए सुरक्षित मार्ग। सड़क के नियमित रखरखाव के बजाय स्थायी समाधान।

जमीन की बात

अमलाई ओसीएम में एक ओर प्रबंधन और आरकेटीसी कंपनी के बेहतर समन्वय से मानसून के बीच भी उत्पादन की रफ्तार कायम है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से अधूरी सड़क विकास की तस्वीर पर सवाल खड़े कर रही है। यदि उत्पादन के साथ कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधाओं पर भी समान प्राथमिकता दी जाए तो यह खदान न केवल उत्पादन बल्कि कार्यस्थल सुविधाओं के मामले में भी एक आदर्श इकाई बन सकती है।

बारिश में पहाड़ी से लुढ़की गोलाकार चट्टान अमरकंटक रोड पर मंडराया बड़ा हादसे का खतरा



धनपुरी के वार्ड क्रमांक 26 सिलपरी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास मुख्य सड़क पर आकर रुका पत्थर, दो भारी वाहन एक साथ नहीं निकल पा रहे धनपुरी। लगातार हो रही बारिश ने अमरकंटक रोड पर खतरा की घंटी बजा दी है। नगर पालिका धनपुरी के वार्ड क्रमांक 26 सिलपरी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप पहाड़ी से एक गोलाकार बड़ा पत्थर लुढ़ककर सीधे मुख्य सड़क पर आ गई, जिससे इस व्यस्त मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। सड़क का बड़ा हिस्सा धिर जाने से एक समय में केवल एक ही बड़ा वाहन निकल पा रहा है, जबकि सामने से दूसरा भारी वाहन आने पर जाम की स्थिति बन जाती है। यह मार्ग धनपुरी, डोगरिया और अमरकंटक को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है,

जहां से प्रतिदिन बसें, कोयला परिवहन करने वाले ट्रक, मालवाहक वाहन और अन्य भारी वाहन गुजरते हैं। सड़क पर विशाल चट्टान पड़े होने के कारण वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि तेज गति से आ रहे किसी वाहन का संतुलन बिगड़ जाए तो कभी भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण मूरूम पहाड़ी की मिट्टी कमजोर हो चुकी है। ऐसे में सड़क पर पड़ा यह बड़ा पत्थर किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। रात के समय और खराब मौसम में यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों ने संबंधित विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा जिला प्रशासन से तत्काल जेसीबी और अन्य मशीनरी भेजकर सड़क से पत्थर को हटाने की मांग की है।

पटवारियों की हड़ताल समाप्त, शासन ने मानी सभी मांगें

ब्यूहारी। तहसील कार्यालय ब्यूहारी-में 3 अगस्त से हड़ताल कर रहे पटवारियों की सभी मांगें मान ली गई प्रमुख मांगों। विभागीय परीक्षा,विना जांच एफ आई आर नहीं, संघ के पदाधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगे आदि सब मांगों को लेकर जो हड़ताल हो रही वह प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा पत्र जारी कर मान लिया गया। इसके बाद संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी एवं वरिष्ठ पदाधिकारी कल्याण सिंह द्वारा हड़ताल समाप्ती की घोषणा की गई। संघ के अध्यक्ष राजेंद्र द्विवेदी ने कहा की शासन की राजस्व विभाग की हितग्राही मूलक योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना हमारा प्रथम लक्ष्य है हड़ताल समाप्ति पर जनता ने राहत की सांस ली है।



वार्ड क्रमांक 4 की नई स्ट्रीट लाइटें बंद, अंधेरे से लोग परेशान

अमलाई। नगर परिषद बकहो के वार्ड क्रमांक 4 में हाल ही में लगाई गई नई स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी हैं। इसके कारण रात के समय वार्ड में अंधेरा पसरा रहता है, जिससे स्थानीय नागरिकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अंधेरे के कारण दुर्घटनाओं और असामाजिक गतिविधियों की आशंका भी बनी रहती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह समस्या केवल वार्ड क्रमांक 4 तक सीमित नहीं है, बल्कि नगर परिषद के लगभग सभी 15 वार्डों में नई स्ट्रीट लाइटों के बंद होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में पूरे नगर परिषद क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था

पर सवाल उठ रहे हैं। जब इस संबंध में नगर परिषद के अधिकारियों से जानकारी ली जाती है तो उनका कहना होता है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा स्ट्रीट लाइट परियोजना का हैंडओवर अभी तक नगर परिषद को नहीं सौंपा गया है।अधिकारियों के इस जवाब के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि परियोजना का हैंडओवर अब तक नहीं हुआ है, तो नई स्ट्रीट लाइटें इतनी जल्दी बंद कैसे हो गई? आखिर किस गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया कि कुछ ही समय में बड़ी संख्या में लाइटें खराब हो गई? नागरिक यह भी सवाल उठा रहे हैं कि यदि हैंडओवर आज तक नहीं हुआ, तो पिछले लगभग डेढ़ वर्षों से इन स्ट्रीट लाइटों का संचालन और रखरखाव किसके जिम्मे था? आखिर इस दौरान लाइटें किसके द्वारा

संचालित की जा रही थीं—संबंधित ठेकेदार या नगर परिषद? यदि बिना औपचारिक हैंडओवर के व्यवस्था संचालित की जा रही थी, तो क्या यह निर्धारित नियमों और शासकीय प्रक्रिया के अनुरूप था? नगर परिषद को इन सभी सवालों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।स्थानीय नागरिकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में गुणवत्ताहीन सामग्री के उपयोग या कार्य में अनियमितता सामने आती है तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही वार्ड क्रमांक 4 सहित नगर परिषद के सभी 15 वार्डों में बंद पड़ी नई स्ट्रीट लाइटों को तत्काल चालू कराया जाए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।

जालसाजों ने खातों से पार किये 1.25 लाख रुपये

हरिभूमि न्यूज़ Kटनी

माधवनगर थाना क्षेत्र में ठगी की दो घटनाएं हुईं। शातिर बदमाशों ने दो बुजुर्गों के बैंक खातों से 1,24,812 की रकम गायब कर दी। पुलिस ने दोनों ही मामलों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार माधवनगर थाना क्षेत्र की सुधारन्यास कॉलोनी निवासी शिवशंकर सिंह 69 वर्ष के बैंक खाते से अज्ञात ठगों ने छल-कपट करते हुए 30,000 की राशि निकाल ली। घटना 5 अगस्त की सुबह करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

दूसरा मामला झिंझरी पुलिस लाइन का है। फरियादी राजेंद्र पटेल 69 वर्ष

माधवनगर पुलिस ने शातिनगर में दबिशा देकर की कार्यवाही

को अज्ञात साइबर ठग ने अपना शिकार बनाया। 4 अगस्त की दोपहर 1:26 बजे के आसपास उनके खाते से धोखाधड़ी कर 94,812 की रकम उड़ा ली गई। 5 अगस्त की शाम पीड़ित ने माधवनगर थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस बैंक ट्रान्जेक्शन डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर अज्ञात साइबर अपराधियों का सुराग लगाने का प्रयास कर रही है।

एक दशक से अधूरी पड़ी सड़क बनी परेशानी का सबब, ओपीएम और नगर परिषद से निर्माण की मांग

अमलाई। स्टेट बैंक से बरम बाबा होते हुए बंबू गेट तक जाने वाली सड़क पिछले एक दशक से अधूरी पड़ी है। यह मार्ग ओरिएंट पेपर मिल्स (ओपीएम) के स्वामित्व का बताया जाता है और इसी रास्ते से कंपनी तक कच्चा माल लेकर भारी वाहन पहुंचते हैं। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण कंपनी कर्मचारियों, स्कूली बच्चों, ग्रामीणों और आम नागरिकों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों के अनुसार करीब एक दशक पूर्व ओपीएम द्वारा इस सड़क का लगभग 75 प्रतिशत निर्माण कराया गया था, लेकिन शेष कार्य आज तक अधूरा पड़ा है। इस दौरान कंपनी में दो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीओओ बदल चुके हैं, लेकिन सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो सका।बंबू गेट के सामने सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आवागमन बाधित रहता है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है, जब ओपीएम पहुंचने वाले भारी वाहनों की कतार



सड़क के दोनों ओर लग जाती है। ऐसे में राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को जोखिम उठाकर निकलना पड़ता है।हाल ही में ओपीएम में नए मुख्य परिचालन अधिकारी

(सीओओ) की पदस्थापना हुई है। ऐसे में क्षेत्रवासियों की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या उनके कार्यकाल में इस लंबे समय से लंबित सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो पाएगा या नहीं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि ओपीएम इस सड़क का निर्माण कराने में असमर्थ है, तो नगर परिषद बकहो को आगे आकर सड़क निर्माण की पहल करनी चाहिए। उनका कहना है कि यह मार्ग जनहित से जुड़ा हुआ है और यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। सड़क की जर्जर स्थिति के कारण दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है। उल्लेखनीय है कि इसी मार्ग पर कई बार दुर्घटना हो चुकी। इसके बाद भी सड़क निर्माण नहीं होना लोगों में नाराजगी का कारण बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने संबंधित अधिकारियों से शीघ्र सड़क निर्माण कराने सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की है।

खबर संक्षेप

धनपत कुमार ने किया जिले का नाम रोशन शोध कार्य के लिए मिली पीएचडी की उपाधि



अमरकंटक। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.) के अर्थशास्त्र विभाग के

शोधार्थी धनपत कुमार को उनके शोध कार्य के लिए पीएचडी की उपाधि प्रदान किया गया। उनके शोध का विषय अनूपपुर जिले में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर अध्ययन था, धनपत कुमार ने यह शोध अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. आनंद सुगंधे (शोध निर्देशक) एवं गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) के अर्थशास्त्र विभाग के सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. राजकुमार नागवंशी (सह-शोध निर्देशक) के संयुक्त निर्देशन में पूर्ण किया। उनके शोध अनूपपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़े ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण के प्रभाव का विश्लेषण किया है। पीएचडी की उपाधि विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय व विभाग के प्राध्यापक, शोधार्थीगण तथा उनके परिवारजन की उपस्थिति में प्रदान की गयी। धनपत कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमगवाँ वि.ख. जैतहरी से तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (माप्र0) से पूर्ण किया है। वर्तमान में धनपत कुमार शासकीय उत्कृष्ट च्चतर माध्यमिक विद्यालय जैतहरी में उच्च माध्यमिक शिक्षक (अर्थशास्त्र) के पद पर कार्यरत है। धनपत कुमार अनूपपुर जिले के तहसील जैतहरी के ग्राम क्यौंठार के निवासी है। उनके पिता प्रेमलाल चौधरी एक भूमिहीन मजदूर है। उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती जंत्री बाई एवं गुरुजन उनके प्रेरणा के स्रोत रहे है। डॉ. धनपत कुमार का यह शोध जिले के ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। उनकी सफलता अनूपपुर जिले के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।

कल से शुरू होगा हर घर तिरंगा अभियान कटनी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के निर्देशों के अनुरक्रम में जिले में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यह अभियान जन-आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें आमजन को देशभक्ति के उत्साह के साथ भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ भी संवेदनशीलता और गरिमा के साथ मनाया जाएगा। जिले में हर घर तिरंगा अभियान के आयोजन हेतु कलेक्टर आशीष तिवारी ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिले में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान 9 से 17 अगस्त तक जनभागीदारी के साथ आयोजित होगा। इस दौरान शासकीय विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विविध गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। नागरिकों से अपने घर, कार्यालय एवं वाहनों पर तिरंगा फहराने तथा अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील की गई है।

कमिश्नर ने स्वास्थ्य शिविर का किया निरीक्षण

अनूपपुर। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत नगर पालिका मुख्यालय बिजुरी में स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर का आज शहडोल संभाग की कमिश्नर श्रीमती सुरभि गुप्ता ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण, दवा वितरण तथा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में आने वाले प्रत्येक हितग्राही को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं सहज स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।



उन्होंने कहा कि आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए मरीजों को समुचित उपचार प्रदान किया

जाए तथा मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने शिविर में उपस्थित चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों से चर्चा कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने, आमजन के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करने तथा अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर श्रीमती अर्चना कुमारी सहित स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के अधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

हरिभूमि न्यूज़ कटनी नगर पालिक निगम द्वारा शहर में सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। इसी क्रम में निगमायुक्त सुश्री तपस्या पहिरार के निर्देशानुसार माधवगगर कैप रोड

स्थित स्पीड ब्रेकरों पर रोड स्टड्स (रिफ्लेक्टर) लगाने का कार्य पूर्ण कराया गया। सिटी ट्रांसपोर्ट मैनेजर योगेश पवार ने बताया कि यह रिफ्लेक्टिव रोड स्टड्स रात्रिकालीन एवं कम दृश्यता की स्थिति में वाहन चालकों को स्पीड ब्रेकरों की पूर्व सूचना प्रदान करेंगे, जिससे चालक समय रहते



वाहन की गति नियंत्रित कर सकेंगे और दुर्घटनाओं की संभावना में कमी आएगी। सड़क सुरक्षा के इन उपायों से आमजन को सुरक्षित आवागमन की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि नागरिकों की सुरक्षित एवं सुचारु आवागमन व्यवस्था नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

माधव नगर के ब्रेकरों में लगाए गए रिफ्लेक्टर सड़क सुरक्षा की दिशा में हुई पहल

सैंदुरी के जंगलों में हर रात सज रही जुए की महफिल



पुलिस की नाक के नीचे खेल, कार्रवाई पर उठे बड़े सवाल खाकी की कार्यशैली कटघरे में, दो सप्ताह से चल रही गतिविधियों की चर्चा

अनूपपुर। जिले में न्वागत पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। इसके बावजूद जिला मुख्यालय के अनूपपुर थाना क्षेत्र से सामने आ रही चर्चाओं ने पुलिस की सक्रियता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप हैं कि थाना क्षेत्र के सेंदुरी के जंगलों और सुरसान इलाकों में

बाढ़ प्रभावित रपटे एवं पुल-पुलिया पार करने का प्रयास न करें-कलेक्टर रत्नाकर झा

अनूपपुर। जिले में हो रही लगातार वर्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर रत्नाकर झा ने नागरिकों से पूर्ण सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वर्षाकाल में नदी-नालों, रपटों एवं पुल-पुलियों पर अचानक जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में जहां भी सड़क या पुल-पुलिया पर पानी बह रहा हो, वहां किसी भी परिस्थिति में उसे पार करने का प्रयास न करें। कलेक्टर श्री झा ने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। तेज बहाव वाले पानी में वाहन चलाना अथवा पैदल निकलना अत्यंत जोखिमपूर्ण है। नागरिक यात्रा पर निकलने से पहले मौसम एवं मार्ग की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें तथा आवश्यकता न होने पर खराब मौसम में यात्रा से बचें। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नदी, नालों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रखने की भी अपील की है। कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल जिला प्रशासन अथवा संबंधित विभाग को सूचना दें तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल में सजगता, धैर्य और जिम्मेदार व्यवहार अपनाकर ही जन-धन की हानि से बचा जा सकता है।

नर्मदा उद्गम से निकली शिवभक्ति की अविरल धारा, 500 कांविरियों ने गूंजाया ‘हर-हर महादेव’



विशाल कांविरिया दल ने नृत्य-भजन के साथ भरी नर्मदा जल की कांवड़ जलेश्वर महादेव और भोरमदेव में होगा जलामिषेक

अमरकंटक। श्रावण मास की पावन बेला में मां नर्मदा की उद्गम स्थली अमरकंटक शुरुवार को शिवभक्ति के विराट उत्सव की साक्षी बनी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के गौरकापा से लगभग 500 कांविरियों का विशाल दल पारंपरिक वेशभूषा में ढोल-नगाड़ों, भजन-कीर्तन और हर-हर महादेव, बोल बम तथा नर्मदे हर के गगनभेदी जयघोषों के साथ अमरकंटक पहुंचा। श्रद्धा और उत्साह से सराबोर इस भव्य काविर यात्रा ने पूरे नगर को शिवमय वातावरण में रंग दिया। कांविरिया दल बाबा रामगिरी धूनी से यात्रा प्रारंभ कर अनुशासित कतारों में नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मां नर्मदा के पवित्र उद्गम स्थल पहुंचा। रास्ते भर श्रद्धालु भगवान शिव के भजनों पर नृत्य करते रहे, जिससे अमरकंटक की आध्यात्मिक फिजा भक्तिरस से सराबोर हो उठी। स्थानीय श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने भी

इस अद्भुत दृश्य का स्वागत किया। नर्मदा मंदिर परिसर में कांविरियों ने विधि-विधान के साथ मां नर्मदा की पूजा-अर्चना कर पवित्र नर्मदा जल अपनी कांवड़ों में भरा। इसके बाद शिव आराधना और कांवर पूजन कर भगवान भोलेनाथ को नर्मदा जल अर्पित करने का संकल्प लिया। श्रद्धालुओं का मानना है कि नर्मदा उद्गम का पवित्र जल भगवान शिव पर चढ़ाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शनिवार, 8 अगस्त को यह विशाल कांविरिया दल श्रावण कृष्ण पक्ष दशमी के अवसर पर भगवान जलेश्वर महादेव के पावन धाम पहुंचेगा, जहां नर्मदा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्र पूजन और विशेष आराधना की जाएगी। इसके पश्चात कांविरिए अपने गृह क्षेत्र लौटते हुए छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर में भी नर्मदा जल अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के कंधों पर कांवर, हाथों में भगवा ध्वज और मुख पर ओम नमः शिवाय, हर-हर महादेव तथा बोल बम के जयघोष निरंतर गूंजते रहे। भक्ति, अनुशासन और उत्साह का ऐसा संगम दिखाई दिया मानो मां नर्मदा की पवित्र धारा स्वयं शिवधाम की ओर प्रवाहित हो रही हो। श्रावण मास में नर्मदा उद्गम से जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करने की यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि नर्मदा और महादेव के सनातन आध्यात्मिक संबंध की जीवंत अभिव्यक्ति भी है। हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस परंपरा का निर्वहन करते हुए अमरकंटक पहुंचते हैं और नर्मदा जल लेकर शिवधामों की ओर प्रस्थान करते हैं। अमरकंटक की पवित्र वादियां देर तक नर्मदे हर... हर-हर महादेव... बोल बम... के जयघोषों से गुंजायमान रहें और शिवभक्ति की यह अविरल धारा श्रद्धा, आस्था और सनातन परंपरा का अनुपम संदेश देती हुई अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ गईं।



अनूपपुर/अमरकंटक। मां नर्मदा की पावन उद्गम स्थली, विंध्य और सतपुड़ा की गोद में बसा देश का प्रसिद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक पर्यटन केंद्र अमरकंटक इन दिनों अपनी खूबसूरती से अधिक शुल्क व्यवस्था को लेकर चर्चा में है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहां दर्शन, आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंचते हैं, लेकिन अब उनकी यात्रा बार-बार कटने वाली रसीदों और अलग-अलग स्थानों पर लिए जा रहे शुल्क के कारण सवालों के घेरे में आ गई है। पर्यटकों का कहना है कि अमरकंटक पहुंचने के बाद ऐसा महसूस होता है मानो हर प्रमुख पर्यटन स्थल पर अलग-अलग शुल्क देना अनिवार्य हो गया है। रामघाट, इंद्रदमन तालाब, सोनमुड़ा, कपिलधारा, ग्लास व्यू-प्वाइंट, झूला पुल और विभिन्न पार्किंग स्थलों पर अलग-अलग मदों में शुल्क लिया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर एक ही पर्यटन क्षेत्र में इतनी जगह अलग-अलग शुल्क लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?

सात जगह शुल्क, लेकिन सुविधा का एक जैसा लाभ नहीं पर्यटकों के अनुसार वर्तमान में रामघाट एवं

इंद्रदमन तालाब के पास पार्किंग शुल्क, दिगंबर जैन सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र में पार्किंग शुल्क, सोनमुड़ा ग्लास व्यू-प्वाइंट शुल्क, रामसेतु झूला पुल का प्रवेश शुल्क, कपिलधारा पार्किंग शुल्क, कपिलधारा ग्लास व्यू-प्वाइंट शुल्क तथा बैरियर पर लिया जाने वाला अलग शुल्क मिलाकर कई स्थानों पर भुगतान करना पड़ता है। यही कारण है कि अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या इन सभी शुल्कों का कोई एकीकृत प्रबंधन है या प्रत्येक स्थान की अलग व्यवस्था है? यदि अलग-अलग शुल्क लिए जा रहे हैं तो उनके बदले मिलने वाली सुविधाओं का मानक भी स्पष्ट होना चाहिए।

सबसे बड़ा सवाल-शुल्क किसका और किसलिए?

पर्यटकों का कहना है कि अधिकांश स्थानों पर यह स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं होती कि शुल्क किस संस्था द्वारा लिया जा रहा है, वह शासकीय है या किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा संचालित है, तथा उससे मिलने वाली सुविधाएं क्या हैं। शुल्क की दर, उसका उद्देश्य और उपयोग सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं होने से लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यदि



व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी हो तो किसी को शुल्क देने में आपत्ति नहीं होगी। बल्कि लोग खुशी से सहयोग करेंगे, क्योंकि पर्यटन स्थलों का रखरखाव और विकास भी आवश्यक है।

वन टिकट, पूरा अमरकंटक की उठी मांग

देश के अलग-अलग राज्यों से आए पर्यटकों ने सुझाव दिया कि अमरकंटक में भी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें प्रवेश के समय एक ही स्थान पर एकीकृत पर्यटन शुल्क लिया जाए। उसी एक टिकट या पास के आधार पर रामघाट, सोनमुड़ा, कपिलधारा, इंद्रदमन तालाब और अन्य प्रमुख स्थलों पर प्रवेश एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उनका कहना है कि इससे बार-बार शुल्क देने की झंझट खत्म होगी, रसीदों का बोझ कम होगा और पर्यटन व्यवस्था अधिक व्यवस्थित तथा आधुनिक बनेगी।

सुविधाएं भी दिखनी चाहिए

पर्यटकों का कहना है कि यदि शुल्क लिया जा रहा है तो उसके बदले पर्याप्त सुविधाएं भी दिखाई देनी चाहिए। पार्किंग स्थलों पर व्यवस्थित पार्किंग, पर्याप्त सुरक्षा, स्वच्छ शौचालय, पेयजल, बैठने की व्यवस्था,

साफ-सफाई, मार्गदर्शन बोर्ड, दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं और भीड़ नियंत्रण जैसी व्यवस्थाएं हर प्रमुख स्थल पर सुनिश्चित होनी चाहिए। विशेषकर रविवार, सावन, नववर्ष और अन्य अवकाश के दिनों में हजारों श्रद्धालु अमरकंटक पहुंचते हैं। ऐसे समय पार्किंग और यातायात व्यवस्था पर भारी दबाव दिखाई देता है। पर्यटकों का कहना है कि यदि शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग इन्हें व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में किया जाए तो सभी को उसका लाभ मिलेगा।

देशभर से आए पर्यटकों की राय

रीवा के रविंद्र सिंह ने कहा कि धार्मिक स्थल पर बार-बार शुल्क देना उचित नहीं लगता। यदि एक बार शुल्क लेकर सभी स्थलों की सुविधा दी जाए तो व्यवस्था बेहतर होगी। कवर्धा के शुभचंद साहू ने कहा कि शुल्क की जानकारी पूरी तरह सार्वजनिक होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि वे किस मद में भुगतान कर रहे हैं और बदले में क्या सुविधा मिलेगी। हैदराबाद से आए केडी राव ने कहा कि अमरकंटक राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल है। यहां आने वाले पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलनी चाहिए। बनारस के राम शिरोमणि ने कहा कि श्रद्धालु सुविधा चाहते

हैं, विवाद नहीं। यदि एकीकृत शुल्क व्यवस्था लागू हो जाए तो लोगों को राहत मिलेगी और पर्यटन भी बढ़ेगा।

पारदर्शिता बढ़ेगी तो बढ़ेगा विश्वास

पर्यटकों का सुझाव है कि प्रत्येक शुल्क केंद्र पर बड़े सूचना बोर्ड लगाए जाएं, जिनमें शुल्क की दर, शुल्क लेने वाली संस्था, उसकी अधिकृतता, प्राप्त राशि का उपयोग तथा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का स्पष्ट उल्लेख हो। इससे भ्रम दूर होगा और लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा। अमरकंटक केवल मध्यप्रदेश का नहीं, बल्कि पूरे देश की आस्था का केंद्र है। यहां आने वाला हर श्रद्धालु और पर्यटक बेहतर अनुभव लेकर लौटना चाहता है। इसलिए अब समय आ गया है कि पर्यटन शुल्क व्यवस्था की समीक्षा की जाए और ऐसी प्रणाली विकसित की जाए, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, पर्यटन का विकास हो और पारदर्शिता भी बनी रहे।

जनता का सीधा सवाल-रसीद के साथ सुविधा कब?

अमरकंटक में उठ रहा मुद्दा केवल शुल्क का नहीं, बल्कि जवाबदेही का भी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि शुल्क लिया जा रहा है तो उसके अनुरूप सुविधाएं भी सुनिश्चित होनी चाहिए। मां नर्मदा की उद्गम स्थली की पहचान जगह-जगह कटने वाली रसीदों से नहीं, बल्कि स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारदर्शी पर्यटन व्यवस्था से होनी चाहिए। अब निगाहें जिम्मेदार विभागों पर हैं कि वे इस जनभावना को किस तरह देखते हैं। क्या अमरकंटक में भविष्य में एकीकृत पर्यटन शुल्क व्यवस्था लागू होगी, या फिर श्रद्धालुओं को हर पड़ाव पर अलग-अलग रसीद कटवानी पड़ेगी? यह सवाल अब केवल पर्यटकों का नहीं, बल्कि पर्यटन प्रबंधन से जुड़ा एक बड़ा जनहित का मुद्दा बनता जा रहा है।